



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2017/वैशाख 5, 1939

No. 115]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2017/VAISAKHA 5, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

(निर्णायक समीक्षा)

मामला सं. एस एस आर 01/2017

विषय: डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करना।

फा. सं. 15/24/2016-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात 'प्राधिकारी' भी कहा गया है), चीन जन गण (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

2. यतः संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात से संबंधित मूल जांच दिनांक 13.06.2011 की अधिसूचना संख्या 14/7/2011-डीजीएडी के तहत प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई थी। अंतिम जांच परिणाम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30.10.2012 की अधिसूचना संख्या 14/7/2011-डीजीएडी के तहत प्रकाशित की गई थी तथा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 51/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 03.12.2012 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

3. यतः वर्तमान याचिका मैसर्स टेक नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (पी) लि., मुंबई (जिसे एतदपश्चात याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने चीन जन गण (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) से डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाने, संशोधन करने

तथा वृद्धि करने के लिए यह आवेदन दायर करने हेतु संबंधित वित्तीय सूचना उपलब्ध कराई है। याचिका निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से है।

शामिल देश

4. इस जांच में शामिल देश चीन जन गण है।

संबद्ध उत्पाद अथवा समान वस्तु

5. वर्तमान जांच में संबद्ध उत्पाद डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स सीमा शुल्क टैरिफ की टैरिफ मद "8442.5020" के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, अन्य शीर्षों जैसे 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.9191 और 7606.9290 के अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं का आयात किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण स्वरूप में सांकेतिक है और जांच के कार्य क्षेत्र पर बाध्यकार नहीं है।

6. प्राधिकारी ने मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"वर्तमान जांच में संबद्ध उत्पाद डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स (जिसे एतदपश्चात डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स अथवा संबद्ध वस्तु कहा गया है) है। डिजिटल प्लेटों का प्रयोग कागज पर अथवा गैर-अवशोषक सबस्ट्रेट्स जैसे पतली चादरों अथवा पॉली फिल्म आदि पर इमेज (डॉट पैटर्न अथवा टेक्स्ट) के रूप में आंकड़े ट्रांसफर करने के लिए प्रिंटिंग उद्योग में किया जाता है। डिजिटल प्लेटों का प्रयोग करने की प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिजिटल वर्क फ्लो लेजर जैसे सदृश्य वर्क फ्लो, जिसके लिए इमेज ट्रांसफर करने के लिए मध्यवर्ती फिल्म अपेक्षित है, का प्रयोग करके कम्प्यूटर से प्लेट (सीटीपी) के रूप में इमेज का सीधे ट्रांसफर करने में सक्षम बनाती है। डिजिटल प्लेटें केमिकल कोटिंग युक्त लीथोग्रेड एल्युमीनियम कॉइलों से कोटेड उच्च शुद्धता से बनी होती हैं। डिजिटल प्लेटें पॉजीटिव (नॉन एक्सपोज्ड एरिया फॉर्म्स इमेज) अथवा निगेटिव (एक्सपोज्ड एरिया फॉर्म्स इमेज) वर्किंग प्लेट हो सकती हैं। कोटिंग कम्पोनेंट को प्लेटों की विभिन्न किस्मों के लिए भिन्न सेनेटाइजर के रूप में भी जाना जाता है।"

7. चूंकि प्रस्तावित जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए संबद्ध उत्पाद का कार्यक्षेत्र वही है, जो मूल जांच में है।

समान वस्तु

8. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

9. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद प्राचलों जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण आदि की दृष्टि से विशेषताएं तुलनीय हैं।

घरेलू उद्योग और आधार

10. याचिका मैसर्स टेक नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (पी) लि. द्वारा दाखिल की गई है। यह कहा गया है कि समर्थनकर्ताओं सहित याचिकाकर्ताओं का उत्पादन देश में संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन का 98 प्रतिशत है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में संबंधित निर्यातकों द्वारा भारत में कोई निर्यात नहीं किया गया है और याचिकाकर्ताओं ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया है। इसलिए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय: के भीतर घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता कंपनी माना है और आवेदन नियमावली के नियम 5 की शर्तों के अनुसार, पक्ष के मानदंडों को पूरा करता है।

निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

11. यतः विधिवत रूप से दायर प्रमाणित आवेदन आवेदन को ध्यान में रखते हुए तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्क के जारी रहने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए तथा यह जांच करते हैं कि इस प्रकार

के शुल्क के समाप्त करने से पाटन जारी रह सकता है अथवा पुनरावृत्ति हो सकती है और घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, की जांच करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

जांच की अवधि

12. आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच अवधि (पीओआई) 01 अक्तूबर, 2015 - 30 सितंबर, 2016 (12 माह) है और क्षति संबंधी जांच अवधि अप्रैल 2011-मार्च, 2012, अप्रैल 2012 से मार्च, 2013, अप्रैल 2013 से मार्च, 2014 और जांच अवधि (पीओआई) की अवधियां हैं। तथापि, प्राधिकारी और अधिक अद्यतन आंकड़ों के आधार पर अपेक्षित विश्लेषण कर सके, इसके लिए प्राधिकारी एतद्वारा जांच अवधि 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 (12 माह) निर्धारित करते हैं। तथापि, क्षति संबंधी जांच अवधि में अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014, अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015, अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016 और जांच अवधि की अवधियां शामिल होंगी। पीओआई के बाद के आंकड़ों की पाटन और क्षति की संभावना निर्धारित करने के लिए जांच की जा सकती है।

प्रक्रिया

13. वर्तमान निर्णायक समीक्षा दिनांक 30.10.2012 की अधिसूचना संख्या 14/7/2011-डीजीएडी (मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम) के तहत प्रकाशित मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलुओं को शामिल करती है।

14. इस समीक्षा में नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधन सहित लागू होंगे।

15. प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय, उत्पादक/निर्यातक को विनिर्माण, उत्पादन और घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री और भारत और अन्य देशों को निर्यात के संबंध में बाजार दशाओं की मौजूदगी को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ, उत्पादक/निर्यातक निम्नलिखित के संबंध में स्पष्टीकरण दे सकते हैं और पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा सकते हैं:

- a) कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।
- b) उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।
- c) उत्पादक/निर्यातक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।
- d) विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातक, भारत में अपने दूतावासों के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

17. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जांच से संबंधित अपने अनुरोध कर सकते हैं। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उसे उपलब्ध कराए जाने हेतु उसका अगोपनीय रूपांतरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

18. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए अनुरोध इस जाँच शुरूआत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच शुरूआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और पाटनरोधी उपाय के जारी रहने अथवा अन्यथा की आवश्यकता के बारे में प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में 'गोपनीयता' का दावा किया जाता है तो दो पृथक सेटों (क) गोपनीय अंकित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) (ख) दूसरा सेट गैर-गोपनीय अंकित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाए। भेजी गई सभी सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर गोपनीय अथवा अगोपनीय स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित किया जाए और सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जाए।

21. गोपनीय अंकित किए बिना सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। गोपनीय रूपांतरण की दो (02) प्रतियां तथा अगोपनीय रूपांतरण की दो (02) प्रतियां सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाएं।

22. गोपनीय दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रस्तुत करने वाले को दी गई सूचना के साथ यह कारण उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा कि इस प्रकार की सूचना क्यों नहीं प्रकट नहीं की जा सकती और/अथवा इस प्रकार की सूचना का संक्षेपण करना संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण का प्रतिरूप होना चाहिए और प्राथमिक रूप से जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया जा रहा है, वह सूचीबद्ध अथवा खाली अथवा सारांशीकृत होनी चाहिए। अगोपनीय सार अनिवार्यतः गोपनीयता आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के तथ्यों को औचित्यपूर्ण ढंग से समझकर अनुमति हेतु पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीयता सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना सार करने के लिए ग्रहणीय नहीं है। उन कारणों का विवरण, जिनसे सार करना संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए अनिवार्यतः उपलब्ध कराए जाएं।

24. प्राधिकारी प्रस्तुत जानकारी के स्वरूप की जांच संबंधी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक है अथवा सूचना प्रदान करने वाला सूचना को सार्वजनिक करने का इच्छुक नहीं है अथवा सामान्य रूप में अथवा सार रूप में इसका प्रकटीकरण करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु इस प्रकार की सूचना को मना कर सकता है।

25. किसी तर्कपूर्ण अगोपनीय रूपांतरण अथवा गोपनीयता का दावे संबंधी किसी ठोस कारण के बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। प्राधिकारी संतुष्ट होने पर और उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर इस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने के लिए पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेगा।

सार्वजनिक फाइलों का निरीक्षण

26. नियम 6(7) की शर्तों के अनुसार, कोई हितबद्ध पक्षकार ऐसी सरकारी फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत अगोपनीय रूपांतरण हो।

असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी इस प्रकार के हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2017

(Sunset Review)

Case No. SSR 01/2017

Subject : Initiation of Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on imports of Digital Offset Printing Plates originating in or exported from China PR

F. No. 15/24/2016-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of “Digital Offset Printing Plates” (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country).

2. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries was initiated by the Authority *vide* Notification 14/7/2011-DGAD, dated 13.06.2011 and the final finding was notified by the Authority *vide* Notification No. 14/7/2011-DGAD dated 03.10.2012. Accordingly Customs Notification No. 51/2012-Customs (ADD) dated 03.12.2012 was issued imposing duty on the basis of reference price.

3. Whereas, the present petition has been filed by M/s Tech Nova Imaging Systems (P) Ltd; Mumbai (hereinafter referred to as Petitioner). The petitioners have provided relevant financial information to file this application for the extension of period, modification and enhancement of existing anti-dumping duties on imports of Digital Offset Printing Plates (hereinafter referred to as subject good) from China PR (hereinafter referred to as subject country).

Country involved

4. The country involved in this investigation is China PR.

Product under Consideration and Like Article

5. The product under consideration in the present investigation is Digital Offset Printing Plates. Digital Offset Printing Plates is classified under Tariff Item ‘8442.5020’ of the Customs Tariff. However, there have been imports of the subject goods under other headings such as 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.9191

and 7606.9290. However, customs classification is indicative in nature and not binding on the scope of the investigation.

6. In the original Final Finding the Authority had noted as follows:

“The product under consideration in the present investigation is Digital Offset Printing Plates (hereinafter referred to as “Digital Plates” or subject goods). Digital Plates are used in the printing industry for transferring data as an image (dot patterns or text) onto paper or on non-absorbent substrates like tin sheets or poly films etc. In the printing process using digital plates, the digital workflow enables direct transfer of image from a ‘computer to the plate’ (CtP) using lasers unlike the analogue workflow that requires an intermediary film to transfer the image. Digital plates are made from high-purity litho-grade aluminum coils coated with a chemical coating. Digital plates may be either positive (non-exposed area forms image) or negative (exposed area forms image) working plates. The coating components, also known as ‘sensitizers’ vary for different types of plates.”

7. Since the proposed investigation is a sunset review investigation, the scope of the product under consideration is the same as that of original investigation

Like Article

8. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

9. Petitioner has claimed that there is no known difference in subject goods exported from subject countries and that produced by the Indian industry. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc.

Domestic Industry & Standing

10. The petition has been filed by M/s Tech Nova Imaging Systems (P) Ltd. It has been stated that the production of petitioners is 98% of Indian production of the subject goods in the Country. On the basis of information furnished by the applicants, the Authority notes that the petitioners have not made any imports of the subject goods from the subject country during the POI. Therefore, the Authority has considered the petitioner company as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

Initiation of Sunset Review

11. WHEREAS, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

Period of Investigation

12. The period of investigation (POI) proposed by the applicant was from 1st October 2015–30th September 2016 (12 months) and the injury investigation period was for the periods April 2011–March 2012, April 2012 to March 2013, April 2013 to March 2014. However, for enabling the Authority to make required analysis on the basis of more updated data, the Authority hereby determines the POI as **1st April 2016 to 31st March 2017 (12 Months)**. The injury investigation period will however, cover the periods, 2013-14, 2014-15, 2015-16 and POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

Procedure

13. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No. 14/7/2011-DGAD dated 03.10.2012.

14. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

15. While submitting questionnaire response, producer/ exporter may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacture, production and sale of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may clarify and provide sufficient information on the following:

- a) Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signal reflecting supply and demand and without significant state interference and weather cost of major inputs substantially reflect market value.
- b) Production costs and financial situation does not suffer from any distortion.
- c) The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
- d) Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

Submission of Information

16. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street, New Delhi – 110001

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

Time Limit

18. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the Domestic Industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.

21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

22. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

26. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

Non-cooperation

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. and Designated Authority